सेन्ट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन

(ए.आई.आई.ई.ए. से संबद्ध)

33, प्रभांजलि, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष : का. एन. चक्रवर्ती

महासचिव : का. डी. आर. महापात्र

परिपत्र क्र. : 3/2021

दिनांक : 01/05/2021

मध्य क्षेत्र के समस्त साथियों के नाम

प्रिय साथियों ,

विषय : मई दिवस अमर रहे ।

135 वीं मई दिवस के उपलक्ष्य में दुनिया और देश के तमाम मेहनतकश जनता के साथ ही बीमा उद्योग के समस्त साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं ।

मई दिवस के समय इस बार जिस कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं , उससे वैश्विक स्तर पर नई-नई चुनौतियों का जन्म हो रहा है। लगातार दूसरे वर्ष भी करोना के प्रकोप से रोज दुखद और पीड़ादायी समाचारों से हम सब दुखी हैं, यह सब सरकार की इस महामारी को समय रहते भांप लेने और इसकी पहले से ही तैयारी करने में विफलता को उजागर करता है। भारत की तस्वीर तो और भयावह है ।निजी अस्पताल दिन दूनी और रात चौगुना मुनाफा कमाकर 'आपदा में अवसर' को चरितार्थ कर रहे हैं। हम एक 'फेल्ड स्टेट' की ओर बढ़ रहे हैं , आर्थिक क्षेत्र में संकट चौतरफा है।

पिउ रिसर्च सेन्टर की रिपोर्ट के अनुसार इस महामारी ने पूरी दुनिया में 5.4 करोड़ मध्यम वर्ग के लोगों को नीचे धकेल दिया है और 13.1 करोड़ लोगों को गरीबी में जीने को मजबूर किया है। भारत में 3.2 करोड़ मध्यम वर्ग से नीचे आ गये हैं और 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गये हैं। गरीबों की संख्या 2020 में 80.3 करोड़ हो गई है। निश्चित तौर पर पूंजीवादी देशों में महामारी की मार और तीव्रतर हुई है। हालांकि समाजवादी देशों की कहानी इससे थोड़ी अलग है। इन देशों ने महामारी को बखूबी नियंत्रित किया है। क्यूबा ने तमाम कठिनाइयों के मध्य न केवल अपने देश में महामारी को नियंत्रित किया वरन् 51 देशों जिनमें इटली जैसे देश भी शामिल हैं , को इसे नियंत्रित करने में सहायता पहुंचाई है। अमरीकी आर्थिक नाकेबंदी के बावजूद उसने 5 वैक्सीन भी विकसित की जिनमें से 3 वैक्सीन का परीक्षण अपने अंतिम दौर में है। वहीं इस मुश्किल आर्थिक गिरावट के दौर में भी चीन ने 2021 के प्रथम तिमाही में 18.3 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज की।

भारत में इस महामारी के दौर में हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में बेड्स का अभाव है , रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है , ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं , वेंटिलेटर भी उपलब्ध नहीं हैं। और यदि लोगों की मृत्यु होती है तो श्मशानों तक में कतार लगी हुई है। यद्यपि डाक्टर्स , नर्सेस ,पैरा मेडिकल स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स , आंगनबाड़ी कर्मी जो वास्तव में करोना से युद्ध लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र है। वैक्सिनेशन की रफ्तार भी अत्यंत धीमी है , विश्व के कई देशों ने वैक्सिनेशन के माध्यम से इस महामारी को मात देने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार द्वारा समूचे स्वास्थ्य के क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया जाता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी व्यय को बढ़ाकर जीडीपी का 6 प्रतिशत कर दिया जाता। परन्तु निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की नीति ने पूरे देश को ही संकट में डाल दिया है। देश के सभी नागरिकों को वेक्सीन तक सरकार मुफ्त में उपलब्ध नहीं करा पा रही है इसके विपरीत सरकार ने तो करोना से जीत का दावा कर अपनी चुनावी सभाओं को बिना किसी सुरक्षा के लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर यही संदेश दिया ।सरकार के मंत्री तक करोना से मुक्ति का दावा करते रहे ।

इन तमाम कठिनाइयों , निराशाजनक समाचारों , संकटों के मध्य एक सकारात्मक घटना भी घटी है। लगभग 45 महीने के बाद एआईआईईए के शानदार संघर्ष से एलआईसी कर्मचारियों ने बेहतरीन वेतन पुनर्निर्धारण हासिल किया। 15 अप्रैल 2021 को आयोजित आभासी सूचना सहभागिता सत्र में एलआईसी के अध्यक्ष ने संगठनों के प्रतिनिधियों को सूचित किया कि 01 अगस्त 2017 से देय वेतन पुनरीक्षण के लिये भा.जी.बी.नि. के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने मंजूर कर लिया है। वेतन पुनर्निर्धारण निश्चित ही कर्मचारियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुकूल है। यह

वेतन पुनर्निर्धारण मौजूदा दौर की सबसे अधिक प्रतिगामी और मजदूर विरोधी वर्तमान सरकार के दौर में हासिल किया गया है, यह निश्चित ही ऐतिहासिक उपलब्धि है। 15 अप्रैल की देर रात सरकार ने वेतन संशोधन को अधिसूचित भी कर दिया। इसके साथ ही वेतन पुनर्निर्धारण के लिये चल रहा संघर्ष का सुनहरा समापन हुआ। ए.आई.आई.ई.ए. ने आरंभ से ही यह तर्क दिया था कि एल.आई.सी. में वेतन पुनर्निर्धारण , संस्थान की वित्तीय ताकत , भुगतान क्षमता और कर्मचारियों की उत्पादकता के आधार पर होना चाहिये। ए.आई.आई.ई.ए. ने हमेशा इस विचार को सर्वोपरि रखा है कि वेतन पुनर्निर्धारण से प्राप्त लाभ न केवल सेवावधि के दौरान प्राप्त हों , बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी इनका मिलना जारी रहे। इसीलिये हमने मूल वेतन में वृद्धि पर अधिक जोर दिया। पिछले वेतन समझौते में भी सरकार के तमाम विरोधों के बावजूद हम मूल वेतन पर एक बेहतर लोडिंग हासिल करने में सफल रहे। इस बार 1 अगस्त 2017 तक के पूरे मंहगाई भत्ते को समाहित करने के बाद 15 प्रतिशत लोडिंग के साथ नये वेतनमान तैयार किये गये। यह एक बहुत बड़ी सफलता है। इसी के साथ हम पांच दिवसीय सप्ताह की अपनी पुरानी मांग को हासिल कर सके।

हम इस शानदार वेतन पुनर्निर्धारण के लिये सभी साथियों को बधाई देते हैं और ए.आई.आई.ई.ए. को कोटिश: धन्यवाद देते हैं। यह सफलता एक कठिन संघर्षों के बाद मिली है। ए.आई.आई.ई.ए. द्वारा सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठनों को इस संघर्ष में शामिल करने की नीति ने भी इस सफलता में एक जबरदस्त योगदान दिया है। एक वर्ग विभाजित समाज में वेतन वृद्धि का संघर्ष सबसे कठिन संघर्ष होता है। यह पूंजी के लिये बढ़ते मुनाफे और कर्मचारियों को उनके कार्य के लिये एक उचित मुआवजे के मध्य एक वर्गीय संघर्ष है।

ए.आई.आई.ई.ए. की स्पष्ट समझ है कि जनकल्याण और नवउदारवाद एक साथ नहीं चल सकता, इसलिये वर्तमान सरकार जो नवउदारवादी नीतियों की पैरोकार है , हमारी न्यायोचित मांगों को स्वीकार करने में श्रमिक हितैषी नहीं हो सकती। श्रम कानूनों को पूंजीपरस्त बनाया जा रहा है , किसानों के संघर्षों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है , विरोध के स्वरों को कुचलने के लिये नये-नये तरीके खोजे जा रहे हैं। निजीकरण के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची बनाई जा रही है, बैंकों के निजीकरण के लिये उन्हें चिन्हित किया जा रहा है।

इस महामारी जैसी आपदा में अवसर तलाशने की प्रक्रिया में एल.आई.सी. का आई.पी.ओ. लाना सरकार की एक प्रीमियम संस्थान को निजीकृत करने की मंशा जाहिर करता है। आज भी इस भयानक मंजर में एल.आई.सी. मार्केट मेंकर और मार्केट लीडर बना हुआ है। अब हम जब वेतन पुनर्निर्धारण जैसे गंभीर मसले का सफलतापूर्वक हल निकाल चुके हैं तो हमें एल.आई.सी. को और अधिक मजबूत बनाने और हमारी एकता को और अधिक सुदृढ़ बनाने में जुट जाना होगा। एल.आई.सी. महज एक व्यापारिक संगठन नहीं है , यह भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है , इसे लोगों द्वारा सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और ए.आई.आई.ई.ए. के लिये एल.आई.सी. एक वैचारिक प्रतिबद्धता है। इसलिये हमें अपने पालिसीधारकों को आश्वस्त करना चाहिये कि हम उन्हें और भी बेहतर सेवा दने के लिये प्रतिबद्ध हैं। अब हमारा ध्यान विनिवेश की सरकारी नीति से लड़ने की ओर केन्द्रित करना चाहिये और हमें एल.आई.सी. आई.पी.ओ. के खिलाफ एक मजबूत जनमत तैयार करना चाहिये।

इस जानदार उपलब्धि के अवसर पर जश्न मनाना स्वाभाविक है। परन्तु हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि देश के लोग आर्थिक और स्वास्थ्य संकट के कारण बड़े पैमाने पर पर पीड़ित हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज लाखों-लाख भाई-बहन अपनी आजीविका खो चुके हैं और हजारों-हजार लोग महामारी का शिकार हो चुके हैं। इस अभूतपूर्व संकट और कष्टों के लिये सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिये। हमारे जोन में कई कर्मचारी-अधिकारी एवं उनके परिजन अपनी जान गंवा चुके हैं। हम सभी मृतकजनों के लिये श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।

मई दिवस के मौके पर पुन: हम विश्व के तमाम मेहनतकशों के साथ एकजुटता का इजहार करते हुए मौजूदा हालातों का हर तरह से मुकाबला करने और अधिक प्रतिबद्ध संघर्ष के संकल्प का उद्घोष करते हैं। मई दिवस के शहीदों को लाल सलाम।

सभी साथियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ-

आपका साथी

(डी.आर. महापात्र)